

असम समझौते का रोडमैप

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

असम समझौते की धारा 6, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971, बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त ज़िला, छठी अनुसूची के तहत असम की स्वायत्त परषिदें, इनर लाइन परमिटि ।

मुख्य परीक्षा के लिये:

न्यायमूर्त बिप्लब कुमार शर्मा समितिकी 52 सफिरशिं, असम समझौते के खंड 6 का प्रभाव ।

स्रोत: द हद्दि

चर्चा में क्यों?

असम सरकार, असम समझौते की धारा 6 के संबंध में न्यायमूर्त बिप्लब कुमार शर्मा समिति द्वारा प्रस्तुत 52 सफिरशिं को लागू करने के क्रम में 25 अक्टूबर 2024 तक एक रोडमैप का मसौदा तैयार करने की योजना बना रही है ।

असम समझौते की धारा 6 क्या है?

■ धारा 6:

- इस समझौते की धारा 6 में असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान एवं वरिसत को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिये संवैधानिक, वधायी तथा प्रशासनिक सुरक्षा का वादा किया गया है ।
- इसका मुख्य उद्देश्य असम के लोगों की स्वदेशी पहचान की रक्षा करना था ।
 - यह धारा जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन और बांग्लादेश से प्रवासियों के आगमन की प्रतिक्रिया में जोड़ी गई थी ।

■ असम समझौता:

- वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एकत्रपिक्षीय समझौता था जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना था ।
- इसके परिणामस्वरूप नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को विशेष रूप से असम के संदर्भ में शामिल किया गया ।

बिप्लब शर्मा समितिकी रिपोर्ट क्या है?

पृष्ठभूमि:

- जुलाई 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समझौते की धारा 6 को लागू करने के तरीके सुझाने हेतु एक 14 सदस्यीय समितिकी गठन किया ।
 - इस समितिकी अध्यक्षता असम उच्च न्यायालय के सेवानवित्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्मा ने की और इसमें न्यायाधीश, सेवानवित्त नौकरशाह, लेखक, AASU नेता तथा पत्रकार शामिल थे ।

असम के लोगों की परभाषा:

- इस समिति ने फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट पूरी की और सफिरशि की कि "असम के लोगों" की परभाषा में नमिनलखिति शामिल होना चाहिये:
 - स्थानीय जनजात
 - असम के अन्य स्थानीय समुदाय,
 - 1 जनवरी 1951 को या उससे पहले असम में रहने वाले भारतीय नागरिक तथा उनके वंशज,
 - असम के स्थानीय लोग

अनुशासकः

- इस समति की 52 सफारशें मुख्य रूप से भाषा, भूमि और सांस्कृतिक वरिसत से संबधति सुरक्षा उपायों पर केंद्रति हैं ।

प्रमुख बढिः

- भूमिः
 - ऐसे राजस्व मंडलों की स्थापना की जाए जहाँ केवल "असम के लोग" ही भूमि का स्वामतिव और हस्तांतरण कर सकें तथा उचित दस्तावेज के बिना भूमि पर कब्जा करने वालों को भूमि का स्वामतिव प्रदान करने के क्रम में तीन वर्षीय कार्यक्रम लागू किया जाए ।
 - चार क्षेत्रों (ब्रह्मपुत्र के किनारे नदी क्षेत्र) का विशेष सर्वेक्षण किया जाए तथा भूमि आवंटन में कटाव प्रभावति लोगों को प्राथमकिता दी जाए ।
- भाषाः
 - असम की स्थानीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये एक स्वायत्त भाषा और साहित्य अकादमी/परषिद की स्थापना की जाए ।
 - राज्य बोर्ड और सीबीएसई के अंतर्गत सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा आठवीं या दसवीं तक असमिया को अनविर्य वषिय बनाया जाए ।
- सांस्कृतिक वरिसतः
 - वत्तिली सहायता के साथ सत्र (नव-वैष्णव मठों) के विकास के लिये एक स्वायत्त प्राधकिरण की स्थापना की जाए ।
 - सभी जातीय समूहों की सांस्कृतिक वरिसत को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परसिर विकसति किये जाएँ ।
 - असम में छठी अनुसूची की स्वायत्त परषिदों (बोडोलैंड प्रादेशिक परषिद, उत्तरी कछार हलिस् स्वायत्त परषिद और कार्बी आंगलॉग स्वायत्त परषिद) द्वारा इन 52 सफारशें को लागू करने पर नरिणय लया जाए ।
 - छठी अनुसूची के क्षेत्रों के साथ-साथ मुख्यतः बंगाली भाषी बराक घाटी को इन सफारशें से छूट दी जाए ।
 - संसद, राज्य वधिनसभा, स्थानीय नकियों और नौकरयों में "असम के लोगों" के लिये आरक्षण दया जाए ।

शामलि न की गई सफारशेंः

- इस समति की कुछ सबसे संवेदनशील सफारशें राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध 52 बढियों में शामिल नहीं हैं जैसेः
 - असम में प्रवेश के लिये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मज़ोरम की तरह इनर लाइन परमटि की शुरुआत ।
 - "असम के लोगों" के लिये आरक्षण ।
 - एक उच्च सदन (असम वधिन परषिद) का नरिमाण, जो पूरी तरह से "असम के लोगों" के लिये आरक्षण हो ।

असम समझौते के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- असमिया पहचान को परभाषति करने की जटलिताः "असमिया लोगों" को परभाषति करने की समति की सफारशि से इस बात पर वविाद हो सकता है कि खंड 6 के तहत सुरक्षा के लिये कौन पात्र है और इससे वभिनिन जातीय समूहों के बीच असंतोष बढ़ सकता है ।
- भूमि स्वामतिव और अधकिरः "असमिया लोगों" द्वारा विशेष भूमि स्वामतिव के लिये राजस्व मंडलों की स्थापना से महत्त्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं । चर क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिये सर्वेक्षण करना तार्ककिक चुनौतियों को प्रस्तुत करता है ।
- भाषा संबंधी नीतियाँः असमिया को आधिकारिक भाषा बनाने तथा वदियालयों में इसे अनविर्य बनाने की आवश्यकता को, विशेष रूप से बराक घाटी जैसे बंगाली-प्रधान क्षेत्रों में, वरिध का सामना करना पड़ सकता है ।
- वत्तिलपोषण एवं प्रबंधनः सत्रों एवं सांस्कृतिक परसिरों के लिये स्वायत्त प्राधकिरण की स्थापना हेतु पर्याप्त वत्तिलपोषण एवं प्रभावी प्रबंधन संरचना की आवश्यकता हो सकती है ।
- राजनीतिक एवं नौकरशाही का वरिधः जनि सफारशें के लिये केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है, उसमें वलिंब या वरिध की संभावना होती है, जिससे कार्यान्वयन प्रक्रिया जटलि हो सकती है ।
- बराक घाटी के लिये छूटः बराक घाटी और छठी अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रों को इन सफारशें से छूट देने से राज्य के भीतर असमानता और वभाजन की धारणा उत्पन्न हो सकती है, जिससे मौजूदा क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है ।

आगे की राह

- हतिधारकों की सहभागिताः
 - "असमिया लोगों" की परभाषा पर आम सहमति बनाने और सफारशें का समावेशी कार्यान्वयन सुनिश्चति करने के लिये वभिनिन जातीय समूहों, नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक संस्थाओं समेत सभी हतिधारकों के साथ नरितर संवाद को बढ़ावा देना शामिल है ।
- चरणबद्ध कार्यान्वयनः
 - कार्यान्वयन के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, उन सफारशें को प्राथमकिता देना जो कम वविादास्पद हों और त्वरति परिणाम देती हों, जैसे कि शिक्षा में भाषा संबंधी नीतियाँ, जबकि धीरे-धीरे भूमि स्वामतिव और पहचान जैसे अधिक जटलि मुद्दों का समाधान किया जाए ।
- क्षमता नरिमाणः
 - स्थानीय अधकिरयों और सामुदायिक नेताओं के लिये भूमि सर्वेक्षण और शीर्षक वत्तिलरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधति करने की क्षमता नरिमाण में नविश करना । इससे पारदर्शति सुनिश्चति होगी और समुदायों के बीच वशिवास का नरिमाण होगा ।

■ संसाधनों का आवंटन:

- सांस्कृतिक प्राधिकरणों और शक्ति सुधारों की स्थापना का समर्थन करने के लिये पर्याप्त धन और संसाधन सुरक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि ये पहल सतत और प्रभावी ढंग से प्रबंधित हों।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: असम समझौता समिति की प्रमुख सफ़ारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा उनके कार्यान्वयन में राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी जटिलताओं पर प्रकाश डालिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. भारत में केवल एक ही नागरकितर और एक ही अधविस है।
2. जो वयकृतर जिनम से नागरकितर हो, केवल वही राष्ट्रधयकष बन सकतर है।
3. जसि वदिशी को एक बर नागरकितर दे दी गई है, कसिी भी परसृथति में उसे इससे वंचति नहीं कयिा जा सकतर।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सर/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/assam-accord-road-map>

